नईदुनिया

फेडरल रिजर्व में व्यापक बदलावों की नींव, 2 फीसदी मुद्रास्फीति लक्ष्य पर दृढ़ प्रतिबद्धता

कड़े संदेश से हिला बाज़ार, अपरिवर्तित दरों पर सख्त बयान

मुंबई

केविन वार्श के अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में पहली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक ने न केवल मौद्रिक नीति में सख्ती का संकेत दिया, बल्कि केंद्रीय बैंक के कामकाज में बड़े संरचनात्मक बदलावों की नींव भी रखी। हालांकि फेडरल फंड दरें 3.5-3.75 फीसदी पर अपरिवर्तित रहीं, 130 शब्दों का बेहद संक्षिप्त बयान और भविष्य के अनुमानों का अभाव उम्मीद से कहीं अधिक सख्त साबित हुआ। वित्तीय बाजारों को कुछ सख्ती की उम्मीद थी, लेकिन बयान के बाद शेयर और बान्ड दोनों बाजारों में गिरावट आई। एफओएमसी के वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुद्रास्फीति दर फेड के 2 फीसदी के लक्ष्य से अभी भी अधिक है और समिति मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है। इसके साथ जारी दाट प्लाट आर्थिक अनुमानों से पता चला कि 18 में से नौ सदस्य इस साल कम से कम 25 आधार अंकों की दर वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जो वार्श के ज्ञात सख्त विचारों के अनुरूप हैं, हालांकि उन्होंने अपने अनुमान प्रस्तुत नहीं किए। बैठक के बाद अपनी पहली प्रेस कान्फ्रेंस में, वार्श ने फेड के संचार, बैलेंस शीट संरचना, डेटा स्रोतों, उत्पादकता और रोजगार, और मुद्रास्फीति ढांचे का अध्ययन करने के लिए पांच कार्य बलों के गठन की घोषणा की। यह कदम वार्श के इस विश्वास को दर्शाता है कि नीति निर्माताओं को कम संवाद करना चाहिए ताकि वे अपने ही शब्दों के कैदी न बन सकें, एक दर्शन जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई बढ़ती पारदर्शिता के विपरीत है। इन कार्य बलों की सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन वैश्विक स्तर पर अन्य केंद्रीय बैंकों की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इन बदलावों के बीच सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि वार्श ने मूल्य स्थिरता और 2 फीसदी मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति फेड की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अपने चिर-परिचित कथन मुद्रास्फीति एक विकल्प है को दोहराया, जिससे उन आशंकाओं को दूर किया गया कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के विचारों के अनुरूप मुद्रास्फीति पर नरम रुख अपना सकते हैं। आने वाले महीनों में ट्रंप की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। इस साल के अंत में संभावित ब्याज दर वृद्धि वैश्विक वित्तीय स्थितियों को और सख्त कर सकती है, जिससे व्यापक आर्थिक परिणाम होंगे।

न्यूज ब्रीफ

अगली पीढ़ी की कार बनाने की तैयारी में किआ सानेट

नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी किआ सानेट अब अपनी अगली पीढ़ी की कार बनाने की तैयारी में है। भारत की सड़कों पर हाल ही में इसके परीक्षण के दौरान देखे गए माडल से यह साफ हो गया है कि किआ अपनी स्थिति और मजबूत करने की तैयारी में है।सूत्रों के अनुसार यह वाहन वर्ष 2027 में भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकता है। इस बार कंपनी केवल बाहरी डिजाइन में बदलाव तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि प्लेटफार्म, तकनीक, केबिन स्पेस और सुरक्षा के स्तर पर भी बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। नई पीढ़ी की सानेट में एक पूरी तरह से नया डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें ऊर्ध्वाधर शैली में लगाए गए मुख्य प्रकाश उपकरण और बूमरैंग जैसी आकृति वाले दिन में जलने वाले प्रकाश इसे अधिक आधुनिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही एक प्रीमियम ग्रिल और मजबूत बंपर भी देखने को मिलेंगे। वाहन के साइड प्रोफाइल को अधिक मस्कुलर बनाया जा सकता है, और इसमें आगे और पीछे दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलने की संभावना है। सबसे बड़ा बदलाव केबिन में देखने को मिल सकता है, जहाँ दो बड़ी 12.3 इंच की स्क्रीन का संयोजन दिया जा सकता है, जो ड्राइवर की जानकारी और मनोरंजन दोनों को संभालेगा। मौजूदा सानेट की पिछली सीट के सीमित स्थान की आलोचना को दूर करते हुए, नए प्लेटफार्म के उपयोग से व्हीलबेस बढ़ने और यात्रियों के लिए अधिक लेगरूम व आराम मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और किआ इसे भारत एन.सी.ए.पी. में पांच सितारा सुरक्षा रेटिंग दिलाने का प्रयास कर सकती है। साथ ही, उन्नत चालक सहायता प्रणालियों (ए.डी.ए.एस.) को भी शामिल किए जाने की संभावना है।

डिविडेंड बंपर: जून के अंतिम सप्ताह में 31 कंपनियां बांटेंगी लाभांश

नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए जून 2026 का अंतिम सप्ताह वित्तीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान देश की 31 प्रमुख कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का लाभ देने जा रही हैं, जो उनके मुनाफे का एक हिस्सा होता है। यह लाभांश निवेशकों के लिए अतिरिक्त आय का एक बड़ा स्रोत बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नजर नियमित आय वाले शेयरों पर रहती है। सप्ताह की शुरुआत 22 जून से होगी, जब पैनासोनिक कार्बन इंडिया (12 रुपए), संगम इंडिया (2 रुपए) और डीएमआर इंजीनियरिंग (0.14 रुपए) डिविडेंड प्रदान करेंगी। इसके बाद 23 जून को एशियन पेंट्स (23 रुपए) और हिंदुस्तान यूनिलीवर (22 रुपए) समेत कई दिग्गज एक्स-डिविडेंड होंगी, जिनमें थायरोकेयर, टाटा पावर भी शामिल हैं। 24 जून को व्हील्स इंडिया और शंकरा बिल्डप्रो का नंबर है। 25 जून सबसे व्यस्त दिन रहेगा, जब 17 कंपनियां लाभांश के लिए एक्स-डेट पर होंगी। इनमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज (25 रुपए) और भारतीय जीवन बीमा निगम (10 रुपए) प्रमुख हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, डिविडेंड का लाभ पाने के लिए निवेशकों को एक्स-डिविडेंड तिथि से पहले शेयर खरीदना अनिवार्य है। भारतीय शेयर बाजार में लागू टी प्लस वन सेटलमेंट व्यवस्था के चलते ये तिथियां अक्सर करीब होती हैं, अतः समय पर निवेश ही डिविडेंड से लाभ कमाने की कुंजी है।

कावासाकी ज़ेडएक्स-10आर पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

नई दिल्ली। बाइक निर्माता कंपनी कावासाकी ने अपनी लोकप्रिय स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, ज़ेडएक्स-10आर पर भारी डिस्काउंट देने की घोषणा की है। डिस्काउंट की वजह से ग्राहकों के लिए इस दमदार सुपरबाइक को खरीदना काफी किफायती हो गया है। इस मोटरसाइकिल को खरीदने पर वर्तमान में अधिकतम 2.89 लाख रुपये तक की भारी बचत की जा सकती है, जो इसे स्पोर्ट्स बाइक प्रेमियों के लिए एक शानदार अवसर बनाती है। ज़ेडएक्स-10आर में 999 सीसी का शक्तिशाली इनलाइन फोर इंजन दिया गया है, जो 202 बीएचपी की जबरदस्त पावर और 112 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करता है। इस उच्च प्रदर्शन वाले इंजन को छह-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो बेहतरीन राइडिंग अनुभव प्रदान करता है। फीचर्स के मामले में भी यह मोटरसाइकिल अत्याधुनिक है।

एआई-डीपफेक से बैंकिंग क्षेत्र में करोड़ों की सेंध, सुरक्षा प्रणालियों को चुनौती

साइबर अपराधी ओपन-सोर्स एआई माडलों से तैयार कर रहे वास्तविक दिखने वाली नकली पहचान

नई दिल्ली

भारत का बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डीपफेक तकनीक के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है। साइबर अपराधी इस उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसी वास्तविक दिखने वाली नकली पहचानें तैयार कर रहे हैं, जो वीडियो केवाईसी और लाइवलीनेस परीक्षण जैसी सुरक्षा प्रक्रियाओं को भी आसानी से भेद रही हैं, जिससे करोड़ों की वित्तीय धोखाधड़ी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई चुनौती वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यह खतरा अब केवल सैद्धांतिक नहीं रहा है। कई वास्तविक मामलों में डीपफेक का उपयोग कर बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा चुका है। जानकारी के अनुसार, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के साथ नकली बैंक स्टेटमेंट और डीपफेक वीडियो के जरिए 15 से 20 करोड़ रुपये तक की धोखाधड़ी की खबर है। तकनीकी विशेषज्ञ बताते हैं कि डीपफेक तैयार करने के उपकरण टेलीग्राम और डार्क वेब पर आसानी से उपलब्ध हैं, और इन्हें सामान्य गेमिंग कंप्यूटर पर भी कम लागत में चलाया जा सकता है, जिससे जालसाजों को संगठित होने में मदद मिल रही है। सबसे गंभीर चिंता यह है कि ये डीपफेक लाइवलीनेस जांच को भी सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं, जो कैमरे के सामने मौजूद व्यक्ति की वास्तविकता सुनिश्चित करती है। यदि यह महत्वपूर्ण सुरक्षा परत विफल होती है, तो डिजिटल केवाईसी की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इस खतरे को देखते हुए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी चेतावनी जारी की है कि अपराधी सुरक्षा उपायों को भेदने के लिए एआई-आधारित तकनीकों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में बैंकिंग क्षेत्र में 48,021 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी अपनी डिजिटल पहचान और उपकरणों की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना होगा। यह खतरा अब केवल बैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ई-कामर्स, सोशल मीडिया और आनलाइन डेटिंग प्लेटफार्म सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।

टीवीएस रोनिन कान्सेप्ट ने खींचा बाइक प्रेमियों का ध्यान

नई दिल्ली। आटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई टीवीएस मोटर की संशोधित रोनिन कान्सेप्ट बाइक ने अपने अनोखे और आक्रामक डिजाइन से मोटरसाइकिल प्रेमियों का ध्यान खींचा था। इसकी तस्वीरें और डिजाइन वाहन प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके उत्पादन संस्करण की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि यह मोटरसाइकिल बाजार में आती है, तो क्या यह बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी या फिर एक सीमित वर्ग तक ही सिमटकर रह जाएगी। संशोधित रोनिन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका आकर्षक डिजाइन है, जिसमें काले, पीले और सुनहरे रंगों का संयोजन इसे पारंपरिक मोटरसाइकिलों से अलग पहचान देता है। इंजन के आसपास का ढका हुआ हिस्सा और रेसिंग प्रेरित स्वरूप इसे भविष्य की मोटरसाइकिल जैसा लुक देते हैं। इसकी स्पोर्ट-शैली की सीट, जो दो हिस्सों में विभाजित दिखाई देती है, प्रीमियम अपील देती है, हालांकि भारत में पीछे बैठने वाले यात्री की सुविधा एक चुनौती हो सकती है। मोटरसाइकिल में दिया गया गोल आकार का मीटर रेट्रो और आधुनिक शैली का मिश्रण है, जिसमें डिजिटल जानकारी और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होने की उम्मीद है। समग्र आक्रामक स्वरूप, अनोखी हेडलाइट और पीले रंग का बड़ा ईंधन टैंक इसे सड़क पर एक विशिष्ट पहचान देने में सक्षम हैं।

केंद्र सरकार ने 16 एफडीसी दवाओं पर लगाया स्थायी प्रतिबंध

कई स्किन क्रीम और एंटीबायोटिक भी प्रतिबंध की सूची में शामिल

नई दिल्ली

देश में दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 16 फिक्स्ड डोज काम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी।

सरकार का कहना है कि इन दवा संयोजनों का कोई ठोस चिकित्सीय आधार नहीं पाया गया और इनके इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते थे। वर्ष 2021 में शुरू हुई गहन जांच प्रक्रिया के बाद विशेषज्ञ उप-समिति ने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और क्लीनिकल डेटा की समीक्षा की।

दवा कंपनियों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। विस्तृत परीक्षण और विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की, जिसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने भी समर्थन दिया। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा संबंधी उत्पादों में उपयोग होने वाले कई काम्बिनेशन, जैसे एलो एक्सट्रैक्ट और विटामिन-ए के मिश्रण शामिल हैं, जिनके सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, अमाक्सिसिलिन और सेराटियोपेप्टिडेज जैसे कई एंटीबायोटिक काम्बिनेशन भी इसकी जद में आए हैं, जिन्हें पर्याप्त चिकित्सीय प्रमाणों के बिना बेचा जा रहा था।

पेट दर्द और ऐंठन के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कुछ अतार्किक मिश्रणों को भी अनुपयोगी पाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतिबंध से न केवल मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि दवाओं के जिम्मेदार और वैज्ञानिक उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

पीयूष गोयल बोले- नौ व्यापार समझौतों ने भारतीय उत्पादों के लिए खोले वैश्विक बाजार

मुंबई। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संभावनाओं वाले देश से आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति बनने तक का आत्मविश्वास भरा सफर तय किया है। इस अवसर पर राज्य सह-मीडिया प्रमुख ओमप्रकाश चौहान और राज्य प्रवक्ता पंकज मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय उत्पादों के लिए नए वैश्विक बाजार खुले हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और खास तौर पर भारतीय उद्यमियों, किसानों, मछुआरों और महिला कारोबारियों के लिए व्यापार के नए रास्ते बने हैं। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया फ्रांस यात्रा के दौरान हुई द्विपक्षीय वार्ताएं और 15 जुलाई से लागू होने वाला भारत-ब्रिटेन एफटीए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निकट भविष्य में बड़े सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के 33 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इनमें कई विकसित देश और ऐसे राष्ट्र भी शामिल हैं जिनके साथ भारत के पहले बहुत करीबी कूटनीतिक संबंध नहीं रहे थे।

भारत का राजकोषीय दुविधा में, क्यों कम पड़ रही है तैयारी

वित्त मंत्री के 3 एफ अपर्याप्त, भारत को चौथे एफ राजकोषीय गुंजाइश की सख्त दरकार

नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा, ईंधन और उर्वरक पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है, जिसे उन्होंने 3 एफ का नाम दिया। हालांकि, आर्थिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को एक चौथे, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण एफ - राजकोषीय गुंजाइश (फिसकल स्पेश) की सख्त दरकार है। उनका तर्क है कि यदि भारत ने अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों में पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश बनाई होती, तो उसके पास अनपेक्षित संकट का सामना करने के लिए कहीं अधिक विकल्प उपलब्ध होते। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड संकट (2022-23) के बाद के तीन अच्छे वर्षों में यदि भारत ने अधिक राजकोषीय गुंजाइश बनाई होती, तो मौजूदा अप्रत्याशित संकट का सामना करने में उसके पास बेहतर विकल्प होते। एक विश्लेषक ने जनवरी 2025 में ही चेतावनी दी थी कि अनुकूल समय में राजकोषीय गुंजाइश न बनाने पर अगला संकट बेतहाशा कठिन होगा। इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, और भारत सीमित विकल्पों के साथ एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। केंद्र सरकार की राजकोषीय घाटे में कमी की राह बहुत धीमी रही है। वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.7 प्रतिशत रहा राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2027 के बजट अनुमानों में 4.3 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि बेहद क्रमिक गिरावट को दर्शाता है। इसी अवधि में, वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में राज्यों का राजकोषीय घाटा भी बढ़ा, जिससे सार्वजनिक ऋण जीडीपी के 80 प्रतिशत से ऊपर ही बना रहा।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस धीमी राजकोषीय सुधार ने निजी निवेश के लिए वित्तीय नियंत्रण को बढ़ाया है और वाणिज्यिक ब्याज दरों को उच्च बनाए रखा है। राजकोषीय घाटे को तेजी से कम करने का एक प्रभावी तरीका निजीकरण था, लेकिन एयर इंडिया की बिक्री के बाद यह प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के एक अध्ययन का हवाला देते हुए विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली महारत्न कंपनियों को छोड़कर, इतने अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बनाए रखने का कोई कारण नहीं है। पहले इन उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन अब जब बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश हो चुका है, तो इन निधियों का उपयोग सार्वजनिक ऋण को कम करने और भविष्य के संकटों के लिए आवश्यक राजकोषीय गुंजाइश बनाने में किया जाना चाहिए।

मारुति सुजुकी अपने ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में

नई दिल्ली

कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी लान्च करने जा रही है, जिसका कोडनेम वाईएमसी है। कंपनी इसे साल 2027 के मध्य तक भारतीय बाजार में उतारेगी। यह नई एमपीवी एसयूवी से प्रेरित एक मजबूत और स्टाइलिश लुक के साथ आएगी, और इसकी सबसे खास बात इसकी प्रभावशाली रेंज होगी, जो एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक हो सकती है।

मारुति की इस नई इलेक्ट्रिक एमपीवी का डिजाइन आम एमपीवी से हटकर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे एसयूवी जैसा ऊंचा फ्रंट, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और रगेड बाडी डिजाइन दिया जा सकता है, जैसा कि टेस्टिंग के दौरान देखे गए माडल में नजर आया। इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स मारुति ई-विटारा से भी मिलते-जुलते हो सकते हैं। इसमें नए अलाय वील्स और एलईडी लाइट्स भी देखने को मिल सकती हैं, जो इसे सड़कों पर एक दमदार उपस्थिति देगी। इंटीरियर की बात करें तो, इसका डैशबोर्ड और केबिन लेआउट भी ई-विटारा से प्रेरित हो सकता है। फीचर्स में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से, इसके टाप वेरिएंट्स में लेवल-2 एडीएएस तकनीक शामिल होने की संभावना है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और आटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे उन्नत फीचर्स होंगे। बैटरी और रेंज के मामले में, यह इलेक्ट्रिक एमपीवी दो बैटरी विकल्पों के साथ आ सकती है। शुरुआती माडल में 49 किलोवाट-घंटे का बैटरी पैक मिलने की संभावना है, जो 142 हार्सपावर की पावर और 193 एनएम का टार्क पैदा करेगा और लगभग 400 किलोमीटर की रेंज देगा। वहीं, बड़े वेरिएंट में 61 किलोवाट-घंटे का बैटरी पैक दिया जा सकता है।